

प्रति,

जनप्रतिनिधित्व विभाग,  
राज्य सचिव,  
सुत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
इलाहाबाद।

राज्य विभाग

रैलगाँव: दिनांक 22, अप्रैल, 2005

विषय: राजाजी साईनारा को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु तहसील सखली  
के ग्राम कुरही में कुल 0.3134 हे० भूमि का अनुमति प्रदान किये जाने के  
सम्बन्ध में।

संदर्भ,

सम्बन्धित पिछले आपके पत्र संख्या-532/भूमि व्यवस्था-भूमि काय-2005 दिनांक  
30 मार्च, 2000 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय  
समलक्षित राजनिष्ठ जो फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु सुत्तरांचल (च०) २०  
जायदारी विभाग एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्यास आदेश,  
2001) (अनुकूलन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की प्रा-154(4)(3)(क)(V) के  
अन्तर्गत तहसील सखली के ग्राम कुरही में कुल 0.3134 हे० भूमि काय करने की अनुमति  
निम्नलिखित शर्तियों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- क्रेता प्रा-120-स को सखीन विरोध श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर  
भूमि में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से  
ही भूमि काय करने को लिये आई होगा।

2- क्रेता जैसा या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि जमाक या  
चुम्बि अनिवार्य कर सखी तथा प्रा-120 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले  
अन्य राजों को भी प्रदान कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा क्रेत की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, दिनांक  
सम्बन्धित भूमि के नियत विस्तार के संजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद  
ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसी प्रारणों से किन्हीं निश्चित रूप में  
अभिलिखित किया जायेगा, उसी अवधि के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की



गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उस क्षेत्रीय किंवा गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय लिया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, छपहार या अन्यथा भूमि का अन्तर्गम करता है तो ऐसा अन्तर्गम उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-187 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके मूल्यामी अनुसूचित जनजाति के न हो और अनुसूचित जाति के भूमिदार होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से निम्नानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके मूल्यामी पारान्गमणीय अधिकार वाले भूमिदार न हो।

6- स्वामित्व किये जा रहे वाले क्षेत्रों में उत्तरांचल के नित्याशियों को 70 प्रतिशत रोजगार/संवावेषन उपलब्ध कराया जायेगा।

7- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से जिस शासन अधिनियम समझता हो, प्रसंगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुरार आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह करें।

भवदीय,

(एमएसएनएमएल)  
प्रमुख सचिव।

संस्था एवं तदुद्दिष्ट।

प्रतिष्ठित निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य सचिव, आयुक्त, उत्तरांचल, मेहरापुर।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल गन्धल, भीडी।
- 3- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4- श्री चान्दिला, पार्टनर सगलार्ड साईन्स प्रिवेट लिमिटेड, पीठ भिहार निगम अर्द्ध नई दिल्ली-82।
- 5- निदेशक, एनआईटी, उत्तरांचल सचिवालय।
- 6- मार्ग मार्गदर्शक।

(आचार्य जी.)  
(सचिव जी.)  
अवर सचिव।